rolite (20) Vermiculite (21) Granite and other dimension stones.

The export of Gold is regulated by the Reserve Bank of India under Gold Control Act.

(c) The Government has not received any reports from the Indian Bureau of Mines or the Department of Mining and Geology, Karnataka for changing the licensing of minerals.

Gap between Control and Market Prices of Essential Commodities

•

*711. SHRI AMAR ROYPRADHAN: SHRI CHITTA MAHATA:

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether Government are aware that at present there is a big gap between controlled and market prices of essential commodities in a climate of scarcity; and

(b) if so, what effective measures Government propose to remove this gap?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) and (b) Prices of most of the essential commodities are not being statutorily controlled. However, certain essential commodities like cereals, sugar, kerosene, soft coke, etc. are being issued to State Governments for public distribution at uniform central issue prices. With a view to reducing the gap between the market prices and the central issue prices, periodical reviews are made to take remedial action relating to production, procurement, transporation and distribution including enforcement of various statutory orders.

राष्ट्रीय मजूरी नीति

*713. **श्री मूलचंद डागा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय मजूरी नीति को लागू करने का है ताकि विभिन्न विभागों में उसी तरह के काम में कार्यरत व्यक्तियों को समान मजूरी मिले और यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकारी कार्यालयों के अतिरिक्त विभिन्न सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले व्यक्तियों को समान काम के लिये समान मजूरी नहीं मिलती है और इसके परिणामस्वरूप सरकार को समय-समय पर हड़तालों और आन्दोलनों का सामना करना पड़ता है और सरकार इस स्थिति से निबटने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) क्या सरकार मजूरी नीति बनाते समय देश की आर्थिक अवस्था और प्रति व्यक्ति आय को ध्यान मे रखेगी ?

•

•

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागो में कार्यरत कर्मचारियों का विद्यमान वेतन ढांचा तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है । आयोग ने अपनी सिफारिशें तैयार करते समय इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान मे रखा था कि विभिन्न विभागों में उसी तरह के काम में कार्यरत व्यक्तियों को समान पारिश्रमिक दिया जाए;

(ख) ऐतिहासिक कारणों से सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों के वेतन ढांचे में विकृतियां हैं । परन्तु सरकार का यह